International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.112-114

cnyko d nkj l xtjrh of'od vFk0;LFkk% dN pukfr;k] dN voljk d lkFk

पीयूष अग्रवाल*

प्रस्तावना

वैष्विक अर्थव्यवस्था का इतिहास यदि देखा जाए तो इसका कभी एक सा प्रतिमान नहीं रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अन्र्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का रूप भी निरन्तर परिवर्तित होता रहा है। अन्र्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व्यापक व संकीर्ण दोनों ही रूपों में प्रचलित रही है। वैष्विक अर्थव्यवस्था का सच्चा रूप/सच्चा अर्थ तो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का उन्मुक्त रूप से एक–दूसरें से जुड जाना, इस क्षेत्र में सूचना, वित्त, पूँजी, प्रौधोगिकी, श्रम आदि का सीमाओं से परे उन्मुक्त प्रवाह/आवागमन, सभी देशों के आयात–निर्यात एवं व्यापार आदि के संबंध में समान नियम, किसी देश/उद्यम को विषेष तरजीह नही, घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय सभी बाजारों पर एक समान नियम लागू होना, समान नियंत्रण आदि है।

लेकिन यह भी तथ्य है कि शाब्दिक अर्थ में वैष्विक अर्थव्यवस्था ना तो कभी रही है और ना कभी रहेगी। हॉ, इसकी तीव्रता में/व्यापकता में घटत–बढत जरूर हो सकती है। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक परिवर्तनशील तत्व है जो वर्तमान में भी बदलाव के मार्ग से गुजर रही है और यह रूप संकीर्णता वाला रूप है, व्यापकता वाला नहीं। जहॉ हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को सषक्त बनाने हेतु संरक्षणवाद की नीति अपना रहा है। बिना अन्य देशों की परवाह किए देशी उघोगों को बढावा देना, आयात किए जाने वाले समान पर शुल्क को बढावा देना, दण्डात्मक शुल्क आदि उभरती हुई प्रवृतियां है।

oreku of'od vFk0;oLFkk d le{k pukfr;k

जैसा कि हम जानते है कि संकीर्णता/अपनी ही सीमाओं में व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्तमान सच है, तों यह भी सच है कि यही संरक्षणवाद की नीतियॉ/स्थानीयकरण/संकीर्णता ही वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मार्ग में सबसें बडी बाधा/सबसे बडी रूकावट है।

हाल ही में अमेरिका व चीन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में किया गया व्यवहार, इसे सिद्ध करता है। दोनों ही महाशक्तियों द्वारा एक–दूसरे से आयात किए जाने वाले सामानों पर भारी शुल्क आरोपित किया गया। भारत के साथ अमेरिका का ''डाटा लोकलाइजेशन'' का मुद्दा चल ही रहा है, तो ऐसे में मेरा प्रश्न यह है कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थ ही रूकावट रहित अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, तो क्या संरक्षण की नीतियॉ इस शब्द को ही खोखला नही कर रही है?

इसके साथ ही विद्यमान शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओ के साथ–साथ अन्य कुछ नई अर्थव्यवस्था भी उभरकर सामने आ रही है जैसे UAE की अर्थव्यवस्था।

oreku e of'od vFk0;oLFkk e fufgr volj

यदि वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ चुनौतियॉ लेकर आई है तो इसी में कुछ अवसर भी निहित है। समय के अनुसार अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना, हर देश के राष्ट्रीय हितो के अनुरूप है ओर एक देश के राष्ट्रीय हितों में एक प्रमुख हित उस देष का आर्थिक विकास, अपने नागरिकों का कल्याण ही है।

---

* सहायक आचार्य, ए.बी.एस.टी. विभाग, सं.मा.पू.भू.जैन राजकीय महाविद्यालय षिवगंज, सिरोही, राजस्थान।

इसीलिए यह संबंधित देश के उद्योगों को बढावा देना, स्थानीय नागरिको को रोजगार आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ है, जिसमें अन्य देशों से व्यापार सीमित किया जा रहा है, खत्म नही। इसी प्रकार नई शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का विश्व पटल पर उभरकर आना भी भविष्य के लिए शुभ संकेत है।

cnyko ds nkSj ls xqtjrh oSf'od vFkZO;LFkk% dqN pqukSfr;k] dqN volj ksa ds lkFk

वैश्विक अर्थव्यवस्था का इतिहास यदि देखा जाए तो इसका कभी एक सा प्रतिमान नहीं रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अर्न्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का रूप भी निरन्तर परिवर्तित होता रहा है। अर्न्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व्यापक व संकीर्ण दोनों ही रूपों में प्रचलित रही है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का सच्चा रूप/सच्चा अर्थ तो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का उन्मुक्त रूप से एक–दूसरें से जुड जाना, इस क्षेत्र में सूचना, वित्त, पूँजी, प्रौधोगिकी, श्रम आदि का सीमाओं से परे उन्मुक्त प्रवाह/आवागमन, सभी देशों के आयात–निर्यात एवं व्यापार आदि के संबंध में समान नियम, किसी देश/उद्यम को विशेष तरजीह नही, घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय सभी बाजारों पर एक समान नियम लागू होना, समान नियंत्रण आदि है।

लेकिन यह भी तथ्य है कि शाब्दिक अर्थ में वैश्विक अर्थव्यवस्था ना तो कभी रही है और ना कभी रहेगी। हॉ, इसकी तीव्रता में/व्यापकता में घटत–बढत जरूर हो सकती है। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक परिवर्तनशील तत्व है जो वर्तमान में भी बदलाव के मार्ग से गुजर रही है और यह रूप संकीर्णता वाला रूप है, व्यापकता वाला नहीं। जहॉ हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को सषक्त बनाने हेतु संरक्षणवाद की नीति अपना रहा है। बिना अन्य देशों की परवाह किए देशी उघोगों को बढावा देना, आयात किए जाने वाले समान पर शुल्क को बढावा देना, दण्डात्मक शुल्क आदि उभरती हुई प्रवृतियां है।

जैसा कि हम सभी जानते है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। डॉलर व्यापार को नियमित, निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। आज के दौर मे भी यह तथ्य है कि अमेरिका आर्थिक दृष्टि से प्रभुता बनाए रखेगा। यघपि संरक्षणवाद/संकीर्णतावाद/व्यापार को सीमित, नियंत्रित करने की नीति के संदर्भ में यह संभव है कि डॉलर का साम्राज्य भी खत्म/सीमित होने के कगार पर आ जाए।

आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का वह समय चल रहा है जबकि जापान, यूरोप, आदि देश, यहॉ तक कि महाद्वीप की ही अर्थव्यवस्था उतार के दौर मे है। यूरोप में आर्थिक संकट विगत वर्षो में हम देख चुके है। ग्रीस, पुर्तगाल जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाऐ ध्वस्त होने वाली स्थिति में थी, यदि समय पर उन्हें बेलआउट पैकेज द्वारा संभाला नहीं जाता। जापान प्राकृतिक संसाधनों से रहित देश है, आर्थिक प्रगति की दृष्टि से जापान विश्व के सामने एक उदाहरण है, लेकिन तुलनात्मक रूप से यह धीरे–धीरे मंद होती जा रही है। इसी प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं मंदी के दौर में हैं। 2017 से लेकर 2019 तक के ऑकडें यही दर्शातें है। 2019 में चीन की सबसे प्रमुख कोशिश ही आर्थिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण की है। अमेरिका चीन ट्रेड वार ने इसे और गंभीर बना दिया है। इस प्रकार यह तो तय है कि वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमें कही भी तेजी/मजबूती/बढत नजर नही आतीं। हर देश अपने स्वार्थो को पूरा करने के लिए सीमित ही रहना चाहता है।

orZeku oSf'od vFkZO;oLFkk ds le{k pqukSfr;k

जैसा कि हम जानते है कि संकीर्णता/अपनी ही सीमाओं में व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्तमान सच है, तों यह भी सच है कि यही संरक्षणवाद की नीतियॉ/स्थानीयकरण/संकीर्णता ही वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मार्ग में सबसें बडी बाघा/सबसे बडी रूकावट है। हाल ही में अमेरिका व चीन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में किया गया व्यवहार, इसे सिद्ध करता है। दोनों ही महाशक्तियों द्वारा एक–दूसरे से आयात किए जाने वाले सामानों पर भारी शुल्क आरोपित किया गया। भारत के साथ अमेरिका का ''डाटा लोकलाइजेशन'' का मुद्दा चल ही रहा है, तो ऐसे में मेरा प्रश्न यह है कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थ ही रूकावट रहित अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, तो क्या संरक्षण की नीतियॉ इस शब्द को ही खोखला नही कर रही है।

यह भी कहा जा सकता है कि हम पुनः एक बार प्राचीन युग में जा रहे है, जहाँ हर राज्य अपने आप में ही सीमित था। स्वयं उत्पादन, स्वयं उपभोग की ही अर्थव्यवस्था थी। कुछ ही राज्यों का अन्य राज्यों के साथ सीमित पैमाने पर व्यापार होता था। लेकिन फिर भी प्राचीन समय आधुनिक समय की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा था, क्योंकि उस समय साधनों का अभाव होने की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं थीं और आज समुचित साधन, टेक्नोलॉजी, जानकारी आदि सभी होते हुए भी जान बूझकर वैश्विक व्यापार के प्रवाह में बाधा पहुँचाई जा रही है, जबकि व्यापार उन्मुक्त होना चाहिए, वैसा ही जैसा एक देश के अन्दर स्वयं में होता है।

वैश्विक मंदी/शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का धीरे–धीरे ध्वस्त होना अपने आप में गंभीर चुनौती है। विश्व संतुलन/व्यापार संतुलन अति–आवश्यक स्थिति है और ऐसा विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती पर ही निर्भर है। यदि ये चरमरा जाएँगी तो दुनिया का आर्थिक ढाँचा ढह जाएगा।

orZeku esa oSf'od vFkZO;oLFkk esa fufgr volj

यदि वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ चुनौतियाँ लेकर आई है तो इसी में कुछ अवसर भी निहित है। समय के अनुसार अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना, हर देश के राष्ट्रीय हितो के अनुरूप है ओर एक देश के राष्ट्रीय हितों में एक प्रमुख हित उस देष का आर्थिक विकास, अपने नागरिकों का कल्याण ही है। इसीलिए यह संबंधित देश के उद्योगों को बढावा देना, स्थानीय नागरिको को रोजगार आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ है, जिसमें अन्य देशों से व्यापार सीमित किया जा रहा है, खत्म नही। इसी प्रकार नई शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का विश्व पटल पर उभरकर आना भी भविष्य के लिए शुभ संकेत है।

लेकिन इसके साथ ही हमारा प्रयास इस दिशा में होना चाहिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वास्तव में मूर्त रूप ले सके। स्वतंत्र वातावरण में विभिन्न देशो की अर्थव्यवस्थाऐ भौगोलिक सीमाओं से आगे बढकर आपस में पूंजी, श्रम, टेक्नोलॉजी सभी साझा कर सके। हमारा उदेश्य मात्र हमारा विकास नही वरन् मानव मात्र का विकास हो। व्यापार पर अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर केवल उचित प्रतिबंध हो, वह भी न्यूनतम मात्रा में – तभी हम वास्तविक रूप से भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के सपने को साकार कर सकते है।

lanHkZ xzUFk lwph

➢ Anderson, J.E., and van Wincoop, E. (2004). Trade costs. Journal of Economic Literature, 42(3), 691-751.

➢ Grossman, G.M., and Helpman, E. (2002). Integration versus outsourcing in industry equilibrium. Quarterly Journal of Economics, 117(1), 85-120

➢ Puga, D., and Trefler, D. (2003). Knowledge creation and control in organizations. (NBER Working Paper No. 9121). Cambridge MA.: National Bureau of Economic Research.

➢ Yeats, A.J. (2001). Just how big is global production sharing? In S.W. Arndt and H. Kierzkowski (Eds.), Fragmentation: New production patterns in the world economy. Oxford, England: Oxford University Press.

❖◆❖